Microfinance Institutions Network (MFIN)

Madhya Pradesh Financial Inclusion Conclave 2018

Coverage Report

25th April 2018

Submitted By:
Perfect Relations

<u>Media Coverage Index</u>

S. No.	Publication Name	Media
1.	The Pioneer	Print
2.	Dainik Jagran	Print
3.	Dainik Bhaskar	Print
4.	Nai Duniya	Print
5.	Hari Bhoomi	Print
6.	Hitvada	Print
7.	Central Chronicle	Print
8.	Agnibaan	Print
9.	Pradesh Times	Print
10.	Pradesh Today	Print
11.	Sandhya Prakash	Print
12.	Sach Express	Print
13.	Swadesh	Print

Publication	The Pioneer
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	10

Gvot taken radical steps for financial inclusion: Sarang

STAFF REPORTER ■ BHOPAL

Jan Dhan is the world's largest financial inclusion programme. The Government has always aimed to bring economic policies keeping in mind economically weaker sections

Government has taken revolutionary steps towards financial inclusion. Jan Dhan is the world's largest financial inclusion programme. The Government has always aimed to bring economic policies keeping in mind economically weaker sections, said Co-operation, Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation (Independent Charges), Panchayat and Rural Development minister Vishwas Sarang at the Microfinance Institutions Network (MFIN) first conclave around Financial Inclusion today in the city.

He raised concern of higher interest rate and suggested to take measure to decrease it.

Principal Secretary, Finance & Commissioner Institutional Finance, Govt. of M.P, Manoj Govil said that state government is trying its best to encourage institutional finance. Finance institutions should try to make their products easily accessible to economically weaker sections. NBFCs contribute significantly in giving better access to services such as insurance, pension and savings to the low income segment.

President, MFIN Rakesh Dubey said that Microfinance has been crucial source of formal credit to the low income segment, providing collateral free unsecured loans. Financial entities such as NBFC-MFIs, Small Bank Finance and Banks have played an important role in furthering the financial inclusion agenda of the government in the state. Despite several entities working together towards furthering this agenda, there are still gaps in easy accessibility to financial services that need to be addressed.

The theme of the event was 'Financial Inclusion - An Imperative for Inclusive Development'.

The discussions also revolved around the role of microfinance and fintech in fostering financial inclusion. S K Bansal, Chief General Manager, NABARD and Sonali Vayangankar, IAS, MD, MP Women Finance and Development Corporation and Rakesh Dubey, President, MFIN were present during the inaugural session.

Publication	Dainik Jagran
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	09

छोटे लोन लेने वालों की वित्तीय स्थिति में सुधार का ध्यान रखें माइक्रोफाइनेंस संस्थान : सारंग

व्यापार प्रतिनिधि, भोपाल। वित्तीय समावेशन की दिशा में केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी काम किया है। जन धन योजना विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंसियल इन्क्लूजन प्रोग्राम है। पिछले चार सालों में केंद्र सरकार ने गरीबो को आर्थिक क्रांति के मध्य में खड़ा कर दिया है। शासन की पूरी योजना है की कमजोर और गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर ही आर्थिक नीति का तानाबाना होना चाहिए। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, के वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही।

श्री सारंग ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस बात पर भी ध्यान दे कि जिन्हें ऋण दिया गया है, उनका विकास भी हुआ है, और 15 हजार के बाद वह 50 हजार और उसके बाद एक लाख रुपए का ऋण लेने लायक बना कि नहीं। अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं। उन्होंने इस अवसर पर माइक्रोफाइनेंस द्वारा लिए जा रहे भारी ब्याज दर भी चर्चा करते हुए कहा कि नावार्ड और अन्य बैंक से सस्ते दर पर ऋण लेकर कमजोर और गरीब वर्ग को सस्ते 3-4 प्रतिशत के ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराएं।

इस अवसर पर एमफिन के अध्यक्ष राकेश कुमार दुबे ने बताया कि अगर बैंक व अन्य संस्थाएं हमें सस्ता ऋण उपलब्ध कराएं तो हम तत्काल इसका लाभ अपने ग्राहकों को देंगे।

Publication	Dainik Bhaskar
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	05

माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से बिना गारंटर लोन

मप्र फाइनेंशियल इनक्लूजन कॉन्क्लेव में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के प्रेसीडेंट राकेश दुबे ने कहा-

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

मप्र में 19 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट (एमएफआई) हैं। राज्य में कुल वित्तीय संस्थानों की संख्या 35 है, जिनमें 5 बैंक भी शामिल हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी कम आय वर्ग के लोगों को गारंटर के बिना ही लोन देती है। यह बात बुधवार को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआइएन) के प्रेसीडेंट राकेश दुबे ने कही। वे भोपाल में एमएफआइएन द्वारा वित्तीय समावेशन : समावेशी विकास के लिए अत्यावश्यक विषय पर बुधवार को आयोजित मप्र फाइनेंशियल इनक्लूजन कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। दुबे ने बताया कि राज्य सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैंक और वित्तीय संस्थान इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रमुख सचिव फाइनेंस एवं कमिश्नर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मनोज गोविल ने हुए कहा कि वित्तीय संगठनों को कमजोर वर्ग के लोगों तक अपने ज्यादा से ज्यादा उत्पाद पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सारंग, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एसके बंसल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कॉन्क्लेव में एमपी वूमन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन की एमडी वयानगनकर, पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की प्रोफेसर डॉ. तारा एस.नायर शामिल हुईं।

Publication	Nai Duniya
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	09

फाइनेंशियल इनक्लूजन कॉन्क्लेव 2018 संपन्न

भोपाल। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूषंस नेटवर्क एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने आज भोपाल में वित्तीय समावेषन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विशय था ''वित्तीय समावेषन:समावेषी विकास के लिए अत्यावष्यक''। विष्वास सारंग, मप्र सरकार ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि षिरकत की और प्रमुख संबोधन के दौरान अपने विचार साझा किये। मनोज गोविल, प्रधान सचिव, फाइनेंस एवं कमिष्नर इंस्टीट्यूषनल फाइनेंस, एमपी सरकार ने इस सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देष्य राज्य में वित्तीय समावेषन की स्थिति का विष्लेशण करना था।

Publication	Hari Bhoomi
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	08

जन धन योजना विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्क्लूजन प्रोग्राम

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

वित्तीय समावेशन की दिशा में केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी काम किया है। जन धन योजना विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्क्लूजन प्रोग्राम है। पिछले चार सालों में केंद्र सरकार ने गरीबों को आर्थिक क्रांति के मध्य में खड़ा कर दिया है। शासन की योजना है की कमजोर और गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर ही आर्थिक नीति का तानाबाना बनना चाहिए।

यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन के वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था वित्तीय समावेशनःसमावेशी विकास के लिए अत्यावश्यक।

- वित्तीय समावेशन पर पहला राज्य-केंद्रित सम्मेलन
- एमएफआईएन ने किया मध्य प्रदेश फाइनेंशियल इनक्लूजन कॉन्क्लेव का आयोजन

एनबीएफसी का लोन पोर्टफोलियो 3529 करोड़ का

मध्य प्रदेश में 35 नियमित वित्तीय संस्थान है जिसमें 19 एनबीएफसी-एमएफआई और 3 एनबीएफसी, 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 5 बैंक शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। इस अवसर पर, एस के बंसल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड और सोनाली वयानगनकर, आइएएस, एमडी, एमपी वुमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन, डॉ. तारा एस नायर, प्रोफेसर, गुजरात इस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, निर्मला बुच, पूर्व मुख्य सचिव और चेयरपर्सन, महिला चेतना मंच, गौतम सिंह, डीजीएम, नाबार्ड, अनुजीत वरदकर, सीईओ, स्वतंत्र माइक्रोफिन, डॉ. आदित्य गैहा, जीएम (डीएनबीएस) आरबीआइ, मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, प्रसीदा कुणाम, सीईओ, समहिता माइक्रोफाइनेंस, ऋषि गुप्ता, एमडी एवं सीईओ, फिनो पेमेंट बैंक, सिद्धार्थ शर्मा, नेशनल हेड, सेल्स, ऐक्सिस बैंक, कल्पना पंत, डायरेक्टर, चैतन्य भी उपस्थित थे।

ऋण लेने वाले का विकास हुआ या नहीं इस पर भी ध्यान दें

विश्वास सारंग ने, कहा कि माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस बात पर भी ध्यान दे कि जिन्हे उन्होंने ऋण दिया है, उनका विकास भी हुआ है और 15 हजार के बाद वह 50 हजार और उसके बाद एक लाख रुपए का ऋण लेने लायक बना है। उसका कल्याण-उत्थान हुआ या वह सिर्फ अपना जीवनयापन करने में ही लगे है। उन्होंने इस अवसर पर माइक्रोफाइनेंस द्वारा लिए जा रहे भारी ब्याज दर भी चर्चा करते हुए कहा कि नाबार्ड और अन्य बैंक से सस्ते दर पर ऋण लेकर कमजोर और गरीब वर्ग को सस्ते 3-4 प्रतिशत के ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराए।

21 लाख परिवारों को साढ़े तीन हजार करोड़ का ऋण

मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव वित्तीय एवं आयुक्त संस्थागत वित्तीय मनोज गोविल ने कहा की राज्य सरकार संस्थागत फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में 21 लाख परिवारों को साढ़े तीन हजार करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। एक वर्ष में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि, वित्तीय संगठनों को ज्यादा से ज्यादा कमजोर वर्ग तक अपने उत्पाद पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए नियम और कायदे बनाने पर भी बल दिया।

माइक्रोफाइनेंस देता है जमानत रहित लोन

एमएफआईएन के प्रेसिडेंट, राकेश दुबे, ने कहा कि, "माइक्रोफाइनेंस न्यूनतम आय वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और जमानत रहित असुरक्षित लोन मुहैया कराता है। एनबीएफसी-एमएफआइज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई कंपनियां इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम कर रही हैं। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई समस्याएं झेली जा रही हैं। इसमें प्रमुख रुप से दूर गांव में अपनी सेवाएं प्रदान् करने मे आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाइयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।"

Publication	Hitvada
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	08

MFIN organises conclave on financial inclusion

■ **Staff Reporter**

MICROFINANCE Institutions Network (MFIN), a self-regulatory organization and an industry association, organised the State's first conclave on Financial Inclusion in State capital on Wednesday.

The theme of the event was "Financial Inclusion - An Imperative for Inclusive Development". Vishwas Sarang, State Minister- Cooperation, Panchayat & Rural Development, was the chief guest of the event. Manoj Govil, Principal Secretary, Finance & Commissioner Institutional Finance, presented the key note address in the conclave.

Minister of State Vishwas Sarang addressing the conclave organised by MFIN in State capital on Wednesday.

Govil underlined that earlier when Jan Dhan accounts of poor people were opened in state, most of them were having the zero balance. Later, these Jan Dhan accounts were connected with government schemes and now they are having some money. He emphasized on the need of drafting rules and regulations for micro financing for secure return.

Minister Vishwas Sarang urged MFIN to see that if loans could be given at lesser rates to poor people. On the other hand, he also vouched for formation of rules and regulations. He also stressed that it should be seen that why the customer who had earlier taken some small loan is not able to take big loan.

On this occasion, MFIN President Rakesh Dubey said that microfinance lends money to low income segment and Madhya Pradesh is having great scope for micro financing.

Publication	Central Chronicle
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	02

MFIN organises MP Financial Inclusion Conclave 2018

Chronicle Reporter, Bhopal

Microfinance Institutions Network (MFIN), a self-regulatory organization and an industry association, organized the state's first conclave around Financial Inclusion today in Bhopal. The theme of the event was "Financial Inclusion - An Imperative for Inclusive Development".

Vishwas Sarang, State Minister- Cooperation, Panchayat & Rural Development, Govt. of Madhya Pradesh was the chief guest at the event and shared his views during the inaugural address. Manoj Govil, Principal Secretary, Finance & Commissioner Institutional Finance, Govt. of M.P presented the key note address at the conclave.

The aim of the conclave was to analyse status of financial inclusion in the state while deliberating upon the challenges and opportunities present in increasing its ambit. The discussions also revolved around the role of microfinance and fintech in fostering financial inclusion.

Mr. S K Bansal, Chief General Manager, NABARD and Ms. Sonali Vayangankar, IAS, MD, MP Women Finance and Development Corporation and Mr. Rakesh Dubey, President, MFIN were present during the inaugural session.

Vishwas Sarang said that the government has taken revolutionary steps towards financial inclusion. Jan Dhan is the world's largest financial inclusion programme. In last four years, the government has brought low income segment population in the midst of economic revolution. The government has always aimed to bring economic policies keeping in mind economically weaker sections.

Manoj Govil, Principal Secretary, Finance & Commissioner Institutional Finance ,Govt. of M.P said that state government is trying its best to encourage institutional finance. Finance institutions should try to make their products easily accessible to economically weaker sections. NBFCs contribute significantly in giving better access to services such as insurance, pension and savings to the low income segment.

According to Mr. Rakesh Dubey, President, MFIN "Microfinance has been crucial source of formal credit to the low income segment, providing collateral free unsecured loans. Financial entities such as NBFC-MFIs, Small Bank Finance and Banks have played an important role in furthering the financial inclusion agenda of the government in the state.

Publication	Agnibaan
Edition	Bhopal
Date	27th April, 2018
Page No.	11

Business

मप्र फाइनेंशियल इनक्लूजन कॉन्क्लेव का आयोजन

भोपाल।

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने बुधवार को भोपाल में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राज्य मंत्री-सहयोग, पंचायत और ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश सरकार विश्वास सारंग, ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रमुख

संबोधन के दौरान अपने विचार साझा किये। उनके अलावा मनोज गोविल, प्रधान सचिव, फाइनेंस एवं कमिश्नर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, एमपी सरकार ने इस सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था।

Publication	Pradesh Times
Edition	Bhopal
Date	27th April, 2018
Page No.	06

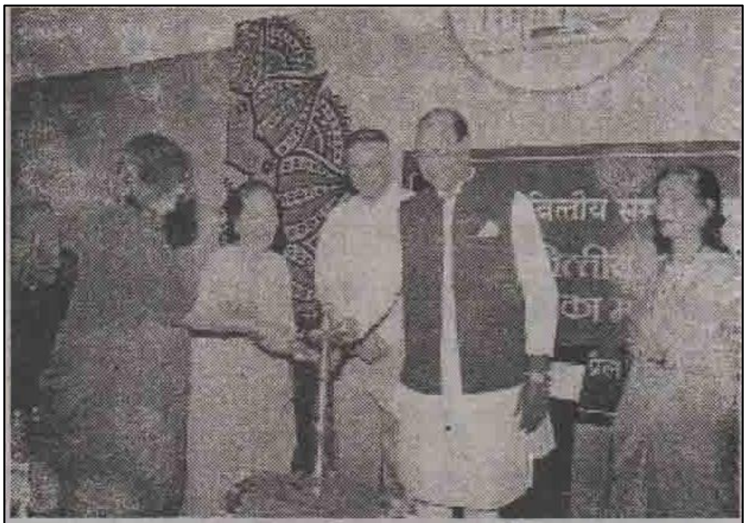

एमएफआइएन ने मध्य प्रदेश फाइनेंशियल इनक्लूजन क्रॉन्क्लेव 2018 का आयोजन किया

भोपाल निप्र। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने आज भोपाल में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था ''वित्तीय समावेशन:समावेशी विकास के लिए अत्यावश्यक''। श्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री-सहयोग, पंचायत और ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रमुख संबोधन के दौरान अपने विचार साझा किये। श्री मनोज गोविल, प्रधान सचिव, फाइनेंस एवं कमिश्नर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, एमपी सरकार ने इस सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। श्री एस के बंसल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड और सुश्री सोनाली वयानगनकर, आइएएस, एमडी, एमपी वुमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और श्री राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा वित्तीय समावेशन के दिशा में केंद्र सरकार ने क्रन्तिकारी काम किया है। जन धन योजना विश्वव का सबसे बड़ा फाइनेंसियल इन्क्लूजन प्रोग्राम है। पिछले चार सालो में केंद्र सरकार ने गरीबो को आर्थिक क्राति के मध्य में खड़ा कर दिया है द्य शासन की पूरी योजना है की कमजोर वर्ग और गरीब वर्गों को धयान में रखके ही आर्थिक नीति का तानाबाना होना चाहिए।

Publication	Pradesh Today
Edition	Bhopal
Date	27th April, 2018
Page No.	09

जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्क्लूजन

भोपाल। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआइएन) ने वित्तीय समावेशन पर

राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय वित्तीय समावेशनः समावेशी विकास के लिए अत्यावश्यक था। विश्वास सारंग, राज्य मंत्री-सहयोग, पंचायत और ग्रामीण विकास ने कहा कि जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इनक्लूजन है। मनोज गोविल, प्रधान सचिव, फाइनेंस एवं कमिश्नर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी उपस्थित रहे।

Publication	Sandhya Prakash
Edition	Bhopal
Date	27th April, 2018
Page No.	10

एमएफआइएन ने मप्र फाइनेंशियल इनक्लूजन कॉन्क्लेव 2018 का आयोजन किया

वित्तीय समावेशन पर पहला राज्य: केंद्रित सम्मेलन

भोपाल • एजेंसी

गरीबो को आर्थिक क्रंति के मध्य में खड़ा कर दिया है द्य शासन की पूरी योजना है की कमजोर वर्ग और गरीब वर्गों को धयान में रखके ही आर्थिक नीति का तानाबाना होना चाहिए।

सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव वित्तीय एवं आयुक्त संस्थागत वित्तीय मनोज गोहिं ने कहा की राज्य सरकार संस्थागत फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वित्तीय संगठनो को ज्यादा से ज्यादा कमजोर वर्ग तक अपने उत्पाद पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में और सरकार के एक्सेस टू क्रेडिट के अलावा, इन्शुरन्स, पेंशन और बचत की सुविधाएं भी गरीब वर्गों को मुहैय्या करने में नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनीज की बड़ी भूमिका है ।

श्री राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, ''माइक्रोफाइनेंस न्यून आय वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और जमानत रहित असुरक्षित लोन मुहैया कराता है। एनबीएफसी-एमएफआइज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई कंपनियां इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच में अभी भी अंतर है जिससे निपटने की जरूरत है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई समस्याएं झेली जा रही हैं जैसेकि सेवायें प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मध्य प्रदेश में 35 नियमित वित्तीय संस्थान है जिसमें 19 एनबीएफसी-एमएफआइ और 3 एनबीएफसी, 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 5 बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआइ का सकल लोन पोर्टफोलियो 3529 करोड़ रूपये का है और यह 21 लाख ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एसएचजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है। इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। श्री नरोत्तम मिश्रा, जन संचार एवं संसदीय मामलों के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख संबोधन दिया। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे - डॉ. तारा एस नायर, प्रोफेसर, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च; श्रीमती निर्मला बुच, पूर्व मुख्य सचिव और चेयरपर्सन, महिला चेतना मंच; श्री गौतम सिंह, डीजीएम, नाबार्ड; श्री अनुजीत वरदकर, सीईओ, स्वतंत्र माइक्रोफिन; डॉ. आदित्य गैहा, जीएम(डीएनबीएस) आरबीआइ, मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय; सुश्री प्रसीदा कुणाम, सीईओ, समहिता माइक्रोफाइनेंस; श्री राजीव अरोड़ा, हेड, जोखिम एवं अनुपालन, जनलक्ष्मी, स्मॉल फाइनेंस बैंक; श्री ऋषि गुप्ता, एमडी एवं सीईओ, फिनो पेमेंट बैंक; श्री सिद्धार्थ शर्मा, नेशनल हेड, सेल्स, ऐक्सिस बैंक; श्रीमती कल्पेना पंत, डायरेक्टर, चैतन्य; श्री धुमिल दलाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड; डॉ आलोक मिश्रा, प्रोफेसर, पब्लिक पॉलिसी एवं गवर्नेंस, एमडीआइ गुड़गांव, और श्री अजय व्यास, एफजीएम सेंट्रल बैंक (कन्वेनर एसएलबीसी), मध्य प्रदेश।

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के विषय में

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआइएन) भारत में माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए एक प्रमुख उद्योग संगठन और सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (एसआरओ) है। इसकी वर्तमान सदस्यता/एसोसिएट्स में देश की 48 प्रमुख एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) और एमएफआइ (एमएफआइज) शामिल हैं। एमएफआइएन विनियामकों एवं अन्य हितधारकों के साथ करीब से कार्य करता है ताकि माइक्रोफाइनेंस के जरिये वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

Publication	Sach Express
Edition	Bhopal
Date	27th April, 2018
Page No.	10

सम्मेलन ॥ एमएफआइएन ने किया मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव का आयोजन

जन-धन योजना विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्क्लूजन प्रोग्राम

वाणिज्य प्रतिनिधि ॥ भोपाल

वित्तीय समावेशन की दिशा में केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी काम किया है। जन धन योजना विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंसियल इन्क्लूजन प्रोग्राम है।

पिछले चार सालो में केंद्र सरकार ने गरीबों को आर्थिक क्रांति के मध्य में खड़ा कर दिया है। शासन की पूरी योजना है की कमजोर और गरीब वर्ग को ध्यान में रखके ही आर्थिक नीति का तानाबाना होना चाहिए। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) एक स्व.विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन के वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास के लिए अत्यावश्यक।

एनबीएफसी-एमएफआई का लोन पोर्टफोलियो 3529 करोड़ का

मध्य प्रदेश में 35 नियमित वित्तीय संस्थान है जिसमें 19 एनबीएफसी एमएफआई और 3 एनबीएफसी, 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 5 बैंक शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। इस अवसर पर एस के बंसल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड और सोनाली ववानगनकर, आइएएस, एमडी, एमपी वुमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन, डॉ.तारा एस नायर, प्रोफेसर, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, श्रीमती निर्मला बुच, पूर्व मुख्य सचिव और चेयरपर्सन भी उपस्थित थे।

21 लाख परिवारों को साढ़े तीन हजार करोड़ का ऋण

इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव वित्तीय एवं आयुक्त संस्थागत वित्तीय मनोज गोयिल ने कहा की राज्य सरकार संस्थागत फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में 21 लाख परिवारों को साढ़े तीन हजार करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। एक वर्ष में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा किए वित्तीय संगठनों को ज्यादा से ज्यादा कमजोर वर्ग तक अपने उत्पाद पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में और सरकार के एक्सेस टू क्रेडिट के अलावा इंश्योरेंस, पेंशन और बचत की सुविधाएं भी गरीब वर्गों को मुहैया करने में नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनीज की बड़ी भूमिका है। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए नियम और कायदे बनाने पर भी बल दिया।

Publication	Swadesh
Edition	Bhopal
Date	26th April, 2018
Page No.	10

एमएफआइएन ने मप्र फाइनेंशियल इनक्लूजन कॉन्क्लेव का आयोजन

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने भोपाल में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था वित्तीय समावेशन समावेशी विकास के लिए अत्यावश्यक। विश्वास सारंग राज्य मंत्री-सहयोग, पंचायत और ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रमुख संबोधन के दौरान अपने विचार साझा किये। श्री मनोज गोविल, प्रधान सचिव, फाइनेंस एवं कमिश्नर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, एमपी सरकार ने इस सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस अवसर पर श्री सारंग ने कहा वित्तीय समावेशन के दिशा में केंद्र सरकार ने क्रन्तिकारी काम किया है। जनधन योजना विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्क्लूजन प्रोग्राम है। पिछले चार सालो में केंद्र सरकार ने गरीबो को आर्थिक क्रांति के मध्य में खड़ा कर दिया है, शासन की पूरी योजना है की कमजोर वर्ग और गरीब वर्गों को धयान में रखके ही आर्थिक नीति का तानाबाना होना चाहिए।